प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

लोकतंत्र अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि अन्य प्रणालियां इससे बदतर हैं।
-जवाहर लाल नेहरु

ममता कह रही हैं कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, लेकिन चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान 98 फीसदी से भी अधिक बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी है।

बंगाल की लड़ाई

चौथे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प यही दिखाती है कि इस राज्य की राजनीतिक हिंसा की संस्कृति में कुछ भी नहीं बदला है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान जहां मुर्शिदाबाद में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की हिंसा में मौत हो गई थी, तो अभी आसनसोल से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की कार पर हमला किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बूथ में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करने के कारण बाबुल सुप्रियो के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। ममता बनर्जी ने बीरभूम में केंद्रीय बलों द्वारा कथित तौर पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है, जबकि हकीकत कुछ और है। वहां केंद्रीय बलों ने कथित तौर पर तृणमूल के कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन लेकर बूथ में जाने से रोकने के लिए हवाई फायर किया था। जैसा कि ममता कह रही हैं कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, लेकिन गौर किया जा सकता है कि चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान 98 फीसदी से भी अधिक बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी है। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक ने तीसरे चरण के मतदान से पहले कहा था कि आज के बंगाल की हालत दस-पंद्रह साल पहले के बिहार जैसी है, जहां निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ती थी। बिहार में स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है और अब वहां संवेदनशील क्षेत्रों में महज 20 फीसदी केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ती है। अपने लंबे शासन के दौरान माकपा ने हिंसा और दबाव की जिस राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया, आठ साल पहले 'परिवर्तन' के नारे के साथ राज्य की सत्ता से उसे बेदखल करने वाली ममता बनर्जी ने इसे खत्म करने के बजाय जारी रहने दिया। पिछले वर्ष हुए पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में भी भारी हिंसा हुई थी, जिसमें सौ से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उस समय विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन भरने तक नहीं दिया गया, जिससे तृणमूल ने 34 फीसदी सीटें निर्विरोध जीत ली थी। तृणमूल जहां भाजपा पर चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ता मतदाताओं को निष्पक्ष ढंग से मतदान करने नहीं दे रहे हैं। यह स्थिति किसी भी रूप में राज्य के हित में नहीं कही जा सकती।

अजीब-सी धुंध है ये

द रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन ऐंड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 2016 ने रेरा की स्थापना की है। लेकिन 4.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 5.75 लाख इकाइयां निर्माण के विभिन्न चरणों में अटकी हुई हैं, जिससे दस लाख से अधिक मतदाता प्रभावित होंगे।

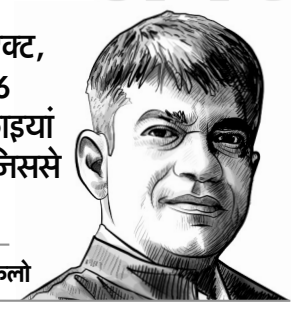

शंकर अय्यर, आईडीएफसी इंस्टी. में विजिटिंग फेलो

जड़ता के साथ ही ऊब बढ़ती जा रही है। और अभी तो 2019 के आम चुनाव के तीन चरण और 150 से भी अधिक सीटों के चुनाव बाकी हैं। तेज होती आवाजों ने अभियान को पटरी से उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बीच, आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे चुनाव के शोरगुल और गुबार में गुम हो गए हैं।

दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में मकानों के खरीदार तेजी से खुद को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं कि उनके पास अपने सपनों के घर का निर्माण पूरा होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वहीं कुछ खरीदार अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उम्मीद और प्रार्थना कर रहे हैं कि फैसला भवन निर्माण किए जाने या रिफंड के रूप में आएगा। बेशक, द रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन ऐंड डेवलपमेंट) ऐक्ट, 2016 ने रेरा की स्थापना की है और बिल्डरों और डेवलपर्स में धोखाधड़ी न करने को लेकर कानून का भय पैदा किया है। लेकिन उनका क्या जो रेरा के अंतर्गत नहीं आते? एनरॉक कंसल्टेंट्स के अनुमान के मुताबिक 4.6 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 5.75 लाख इकाइयां निर्माण के विभिन्न चरणों में अटकी हुई हैं, जिससे दस लाख से अधिक मतदाता प्रभावित होंगे। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे दिवालिया आईएल ऐंड एफएस को दिए कर्ज के ब्योरे घोषित करें, वह भी उसके भीतर पनप रही गड़बड़ियों के सामने आने और अंततः दिवालिया होने के नौ महीने बाद। इस विवादास्पद छद्म बैंक पर कर्जदाताओं का 94,216 करोड़ रुपये बकाया है और नया बोर्ड चाहता है कि इसका 90 फीसदी माफ कर दिया जाए। बैंकों और बचतकर्ताओं तथा जमाकर्ताओं का जोखिम करीब पचास हजार करोड़ रुपये का है और इसमें से 35,382 करोड़ रुपये पहले से संकट में फंसे सार्वजनिक बैंकों के हैं। वैज्ञानिकों ने संभवतः यह बताने में सफलता हासिल कर ली है कि आखिर ब्लैक होल कैसा दिखता है। वहीं भारत के बैंकर ब्लैक होल्स की शिनाख्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो अप्रैल को फंसे कर्ज (एनपीए) से संबंधित रिजर्व बैंक के 12 फरवरी, 2018 के परिपत्र को रद्द कर दिया। नतीजतन कर्ज के रूप में दिए गए 3.2 लाख करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को अब परिभाषित नहीं किया जा सकता, अब न यह अच्छा है या बुरा। आखिर यह मुद्दा क्यों? भारत के बैंकों में जनता का 125 लाख करोड़ रुपये उनके खातों में जमा है। हां, यह जमा बीमा के जरिये सुरक्षित है, लेकिन अहम तथ्य यह भी है कि बीमा के तहत सिर्फ एक लाख रुपये का कवर है, बीमित खातों का मूल्य है 32,75,300 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2018 तक डिपाजिट इंश्योरेंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के पास कुल 81,430 करोड़ रुपये थे। हां, निहित सरकारी गारंटी है, लेकिन नियामकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी बात कहें ताकि प्रणालीगत सुरक्षा किसी सनक का शिकार न हो। जरा इस पर गौर करें जेट एयरवेज ने पिछले हफ्ते अपने विमान जमीन पर उतार दिए, जोकि 18 महीने से संकट से जूझ रही थी और जिस पर कर्जदाताओं का 12,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। इस फंसे कर्ज का बड़ा हिस्सा जिन सरकारी बैंकों का है, उन्हें अभी यह एलान करना है कि ये खराब कर्ज है, क्योंकि वे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं!

सिर्फ बैंकों की बात नहीं है। कुछ हफ्ते से म्यूचुअल फंड भी अपने यूनिट धारकों को उनके निवेश को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में बता रहे हैं, खासतौर से फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के बारे में जो कि मध्य वर्ग का सबसे पसंदीदा निवेश है। सार यह है कि भारत की वित्तीय व्यवस्था में ढांचागत खामी है - दीर्घकालिक ऋण के लिए अल्पकालिक निधियों का उपयोग। जब विनियामक का रवाई से तंग आ चुके बैंक, उधार नहीं दे सकते थे, तो उधारकर्ताओं को गैर-बैंक-वित्त कंपनियों द्वारा सेवा दी जाती थी, जो फिर से बैंकों, जमाकर्ताओं और म्यूचुअल फंड से उधार लेते थे। म्यूचुअल फंड की चिंता यह है कि क्या पैसा वापस आएगा। इस वर्ष जनवरी में रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने छह म्यूचुअल फंड को आईएल ऐंड एफएस के सात हजार करोड़ रुपये के बकाए की वजह से निगरानी सूची में रखा था। इस महीने की शुरुआत में क्रिसिल ने डीएचएफएल की रेटिंग गिरा दी, क्योंकि वह फंड जुटाने में कमजोर दिख रहा है।

एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी) द्वारा जारी किए गए कर्ज में म्यूचुअल फंड का निवेश उनके कर्ज और हाइब्रिड फंड में 3.2 लाख करोड़ रुपये है। क्रेडिट सुसी की पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट के मताबिक इसमें से 1.3 लाख करोड़ रुपये का भुगतान अगले तीन महीने में नियत है। रेटिंग कार्रवाई, बढ़ता दबाव और कमजोर तरलता ने सार्वजनिक बचत को जोखिम में डाल दिया है। सात राज्यों, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड ने इन राज्यों के 90 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया है। मौसम का अध्ययन करने वाले और जलविज्ञान की परिस्थितियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का आकलन है कि भारत का 40 फीसदी हिस्सा सूखे से जूझ रहा है। भारत में वास्तविक समय में सूखा अनुमान प्रणाली का प्रबंधन करने वाले आईआईटी गांधीनगर के वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत का 47 फीसदी हिस्सा सूखे का सामना कर रहा है। चुनाव अभियान का कारवां विश्व जल दिवस से होकर गुजर चुका है। किसानों की हताशा का जिक्र हुआ है, लेकिन न तो कोई फौरी राहत और न ही दीर्घकालीन समाधान को शोर शराबे से भरे प्रचार अभियान में कोई जगह मिली है। चुनाव का लंबा दौर भी लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। चुनाव आयोग को चुनाव की व्यापकता और उसकी जटिलता के प्रबंधन के लिए दुनियाभर से उचित ही प्रशंसा मिली है। समान रूप से चुनाव आयोग को पूरे देश में शासन को 73 दिनों के लिए ठप कर देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 11 अप्रैल को वोट डाले गए थे, लेकिन उन्हें 42 दिनों के बाद ही नई सरकार मिल सकेगी, जब 23 मई को नतीजे आएंगे। हेनरी एडम्स के शब्दों में सवाल करें तो क्या चुनाव अभियान भाषणों से भरा हुआ नहीं है और भाषण खोखली बातों से?

अंतर्ध्वनि

>> शेरजंग गर्ग

टी हाउस हमारा ड्रॉइंग रूम भी था और डाइनिंग हॉल भी

नई दिल्ली के कनाट प्लेस में रीगल सिनेमा और गेलार्ड, खादी ग्रामोद्योग के ठीक दाहिने कोने पर, संसद मार्ग के बाएं कोने पर और जीवन भारती भवन के सामने बाईं दिशा में कभी यानी आज से साढ़े चार दशक पहले साहित्यकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं का एक अड्डा टी हाउस के नाम से हुआ करता था। टी हाउस की यादों का यह सिलसिला सन साठ की गर्मियों से शुरू होता है। उन दिनों मैं अपने परम आत्मीय मित्र, प्रख्यात लेखक एवं छायाकार ब्रह्मदेव की सिफारिश पर दिल्ली प्रेस में नौकरी पा गया था और सरिता में काम करने लगा था। दफ्तर से छूटते ही हमारे कदम टी हाउस की तरफ बढ़ जाते थे। हम लोगों की मित्र-मंडली में कथाकार सुरेंद्र कुमार मल्होत्रा का जलवा कुछ अलग किस्म का था। विश्वविद्यालीय जीवन में उन्हें कहानी लिखने का चस्का लग गया था। उनकी महत्त्वाकांक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन दिनों मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव और कमलेश्वर को अपने प्रबल प्रतिद्वंद्वियों के रूप में देखते थे और व्यक्तिगत मुलाकातों में इस त्रयी की कथा राजनीति की आलोचना किया करते थे। उन्हें इस बात का मलाल भी था कि उनके घनिष्ठ मित्रों में रामावतार त्यागी, बालस्वरूप राही और शेरजंग गर्ग केवल कवि थे, अन्यथा वह भी अपनी चौकड़ी बना सकते थे। वास्तव में टी हाउस की यादों की परतें इतनी सघन हैं कि एक याद समेटते हैं तो दूसरी उभर आती है। यादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। वास्तविकता तो यह है कि टी हाउस हम लोगों के लिए लगभग दूसरा घर था, दफ्तर से छूटकर जाने पर बैठकें जमाने का अड्डा था, दोस्त-मुलाकातियों से भेंट करने की जगह थी, गपशप करने, दुख-दर्द बांटने, दिल बहलाने की स्थली थी। टी हाउस हमारा ड्रॉइंग रूम भी था और डाइनिंग हॉल भी।

-दिवंगत हिंदी साहित्यकार।

मंजिलें और भी हैं

>> रितिका भट्टाचार्य

विश्व बैंक की नौकरी छोड़ लोगों की बेहतरी में लगी

मैं राजनीतिक परिवार से हूं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे विश्व बैंक में नौकरी मिली। कुछ समय तक नौकरी से मैं बहुत खुश रही। पर कुछ समय के बाद काम करने का मेरा उत्साह फीका पड़ता जा रहा था। हालांकि मैं अपनी नौकरी से खुश और संतुष्ट थी। लेकिन मैं नौकरी के अनुशासन से बंधे रहने के बजाय भारत लौटकर कुछ ऐसा काम करना चाहती थी, जो सार्थक हो। मैं पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैंने भारत आकर स्वनीति इनीशिएटिव नाम से एक संस्था गठित की। भारत में विकास के लिए फंडिंग होती है, इसके बावजूद विकास कार्य न होने की शिकायतें आम हैं। मैं अपनी संस्था के जरिये इसका पता लगाना चाहती थी कि विकास के लिए आया पैसा कहां खर्च होता है, खर्च होता भी है या नहीं।

पहला काम मैंने यह किया कि सांसदों से मिलने-जुलने लगी। चूंकि उनमें से ज्यादातर मेरे पिता से परिचित थे, इसलिए अलग-अलग सांसदों के साथ मुलाकात करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यह देखना चाहती थी कि वे क्या काम करते हैं, उनके इलाके में विकास कार्य कितना और किस तरह हुआ है, आदि। मैंने कृषि, शिक्षा, आजीविका, नवीनीकृत ऊर्जा, समाज कल्याण, पेयजल, स्वास्थ्य और पोषाहार जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग सांसदों के कामकाज का अध्ययन करने के साथ-साथ उनका ब्योरा रखना शुरू किया। मैंने उत्तराखंड का दौरा करते हुए पाया कि रोजगार की संभावनाएं न होने के कारण बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। पिंडर घाटी में सात सौ लोग रोजगार विहीन थे। जबकि वहां ढांचागत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाएं थीं, और इस मद में 70 लाख रुपये आवंटित भी हो चुके थे। पर प्रशासन उदासीन था और लोगों को इन योजनाओं के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। प्रशासन से मिलकर मैंने उन्हें यह काम तत्काल शुरू करने के लिए कहा, ताकि विकास कार्यों के साथ स्थानीय युवाओं को, अस्थायी ही सही, लेकिन रोजगार तो मिले। ऐसे ही ओडिशा के पुरी में एक निर्माण परियोजना के लिए सात सौ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुकने के बाद भी आवंटित राशि का 75 प्रतिशत बिना इस्तेमाल के पड़ा था। हमारी संस्था के हस्तक्षेप से वहां काम शुरू हो पाया। झारखंड के गोड्डा जिले में माओवादी प्रभाव वाले एक गांव से नजदीकी रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में आठ घंटे लगते थे, जो स्थानीय लोगों के लिए बेहद कष्टकर था। वहां भी हमने जरूरी हस्तक्षेप किया।

मैंने सत्रह राज्यों में काम किया है और सौ करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी फंड का इस्तेमाल कराया है।

आज मेरी संस्था का प्रसार राज्य सरकारों और जिला प्रशासन तक हो गया है। अब तक मैंने देश के सत्रह राज्यों में काम किया है, सौ करोड़ रुपये से अधिक के बगैर इस्तेमाल वाले सरकारी फंड का हमने इस्तेमाल कराया है, और इस प्रक्रिया में अनुमानतः पचास लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। सरकारें विकास और जनता की बेहतरी के नाम पर सत्ता में आती हैं, लेकिन बहुत काम नहीं हो पाते। इसकी वजह भ्रष्टाचार भी है, सरकारी अधिकारियों की काहिली भी और जरूरी कर्मचारियों का अभाव भी। लेकिन यह देखने की कोई व्यवस्था तो होनी ही चाहिए कि सरकार द्वारा आवंटित पैसे भी जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। इस देश में स्वनीति इनीशिएटिव जैसी अनेक संस्थाओं की जरूरत है।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

पंचायती राज व लोकसभा चुनाव

पंचायतों को सशक्त करने का अर्थ लोकतंत्र को मजबूत करना तथा स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाना व उनको लागू करना है। ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि इसका असर चुनावी नतीजे पर पड़ेगा।

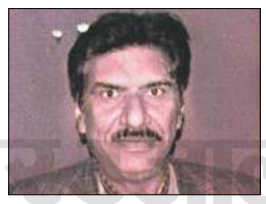

महीपाल

लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। विभिन्न संस्थाएं और मीडिया इन चुनावों के नतीजों के बारे में अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, पर अधिकतर राय निष्पक्ष नहीं हैं। कोई यह नहीं देख रहा कि देश की लगभग 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। वहां पर पंचायतें स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के चुनावों में मतों का प्रतिशत भी शत प्रतिशत होता है। पर पंचायतों की ओर कोई ध्यान नहीं है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा पंचायतों की ओर ध्यान न देना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

राजनीतिक दल किसानों एवं मजदूरों का वोट लेने के लिए अनेक तरह के वादे कर रहे हैं। कांग्रेस ने साल में 72,000 रुपये गरीबों के खाते में डालने का वादा किया है। भाजपा ने साल में 6,000 रुपये छोटे एवं सीमांत काश्तकारों के खाते में डालने का वादा किया और पहली किस्त उन्हें दे भी दी। पर उसे पता नहीं कि यह प्रयास घोड़े के सामने गाड़ी खड़े करने जैसा है। अधिकतर छोटे एवं सीमांत किसान खुद खेती न कर बटाई पर जमीन अन्य को देते हैं।

चूंकि बटाई वाला किसान जोखिम झेलता है, अतः उसे ही यह पैसा मिलना चाहिए था। इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। अगर गांवों में पंचायतों को हस्तांतरित होने वाले पैसे की बंदर बांट न हो, तो किसानों या मजदूरों को अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। 14 वें वित्त आयोग द्वारा दो लाख करोड़ से अधिक पैसा सिर्फ ग्राम पंचायतों को जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का 2018-19 का बजट प्रावधान लगभग एक लाख पंद्रह हजार करोड़ था। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पैसा पंचायतों को जाता है। ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्य की कोई भागीदारी नहीं है। देश में करीब छह लाख गांव हैं, और करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतें हैं। इनमें ग्राम पंचायत के अध्यक्षों को छोड़कर अन्य की भागीदारी न के बराबर है। वार्ड सदस्य असंतुष्ट हैं, क्योंकि गांव के विकास में कोई भागीदारी नहीं है। एक तिहाई से अधिक महिलाएं पंचायतों में विभिन्न पदों पर हैं, पर उनकी भी भागीदारी नहीं है।

ग्राम पंचायतों की बैठकों में वार्ड सदस्यों को बुलाया ही नहीं जाता। प्रत्येक महीने ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए, पर ऐसा कहीं नहीं होता। ग्राम पंचायत में कितना पैसा किस-किस मद के लिए आ रहा है और कहां-कहां खर्च हो रहा है, वह गांव में बोर्ड या दीवार पर लिखा जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण उसे देख सकें। स्पष्ट है कि सांसद या नेता इस पर ध्यान नहीं देते, जिसका नतीजा इस चुनाव में सामने आएगा।

साफ है कि 'सबका साथ सबका विकास' मात्र नारा है। अभी दिया गया नारा, मैं चौकीदार हूं, तेजी से चलन में है। गांवों के अनेक युवा खुद को चौकीदार कह रहे है। मैं उनसे पूछता हूं कि अगर वे चौकीदार हैं, तो गांवों में पंचायतें सही कार्य क्यों नहीं कर रहीं, उसकी निगरानी करें। क्यों पैसा उचित प्रकार से विकास कार्यों में नहीं लग रहा है, उसकी जांच करें।

राजनीतिक पार्टियों द्वारा पंचायतों की कार्यवाही अधिनियम के अनुसार क्रियात्मक करने की जरूरत है। इस समय पैसे से ज्यादा जरूरी है भागीदारी। पंचायतों को सशक्त करने का अर्थ लोकतंत्र को मजबूत करना तथा स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाना व उनको लागू करना है। ऐसा नहीं हुआ है और पंचायतें व ग्राम सभाएं खुद को ठगी गई महसूस कर रही हैं। इसका असर चुनावी नतीजे पर पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है।

हरियाली और रास्ता

श्याम बाबू, पिहू और मीठे सेब

एक मासूम लड़की की कहानी, जो भोली ही नहीं, दिल की भी अच्छी थी।

श्याम बाबू अपने दफ्तर के सम्मानित मैनेजर थे। उच्च वर्ग के अधिकारी तो उनका आदर करते ही थे, दफ्तर में वह इकलौते ऐसे शख्स थे, जिनका निचले वर्ग के कर्मचारी भी सम्मान करते थे। वह सभी को समान भाव से देखते थे। उनका परिवार भी बहुत मिलनसार था।

एक दिन वह अपनी बेटी पिहू के साथ पार्क में गए। पिहू दस साल की थी और ज्यादातर समय अपनी मां के साथ बिताती थी। श्याम बाबू और पिहू देर तक पार्क में बैडमिंटन, फुटबॉल, पकड़म-पकड़ाई आदि खेलते रहे। तभी वहां से एक सेब वाला गुजरा। पिहू ने श्याम बाबू से सेब खाने की इच्छा जताई। श्याम बाबू ज्यादा पैसे लेकर नहीं निकले थे। इसके बावजूद उन्होंने पिहू के लिए दो सेब खरीद लिए। पिहू खूब खुश हुई। श्याम बाबू ने मजाक में कहा, पिहू, एक सेब तुम खा लो और एक पापा को दे दो। यह सुनते ही पिहू के हावभाव बदल गएव। उसने एक सेब उठाया और गप्प से काट लिया। फिर दूसरा सेब भी वह काटने लगी। श्याम बाबू हैरान रह गए। वह सोचने लगे, मैंने तो हमेशा चाहा कि पिहू हर चीज बांटकर खाए। जाने क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में कि आज पिहू ऐसी हो गई। पिहू की मां तो ऐसा नहीं सिखा सकतीं। जरूर यह रजनी का काम होगा। रजनी उनके यहां आया थी। तभी उन्होंने देखा कि पिहू ने दाएं हाथ वाला सेब श्याम बाबू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पापा, आप यह सेब खाइए, यह ज्यादा मीठा और रसीला है। श्याम बाबू बोले, पर पिहू, तुमने तो दोनों सेब जूठे कर दिए। पिहू बोली, पापा जूठे नहीं किए। मैं तो सिर्फ यह देख रही थी कि कौन-सा सेब ज्यादा मीठा है। रजनी आंटी कहती हैं कि जब किसी को कुछ देते हैं, तो जो सबसे अच्छा हो, वही देना चाहिए। श्याम बाबू समझ गए कि वह कितने गलत थे।

सच्चाई जानने से पहले कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

खुली खिड़की

देशों की प्रशासकीय भाषाएं

विश्व में कई तरह की भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। कुछ भाषाएं कई देशों की आधिकारिक या प्रशासनिक भाषा बन चुकी हैं। इनमें अंग्रेजी 59 देशों के साथ पहले स्थान पर काबिज है।

*हिंदी भाषा 13 देशों में बोली जाती है पर सरकारी उपयोग प्रमुखतः तीन देशों में होता है।

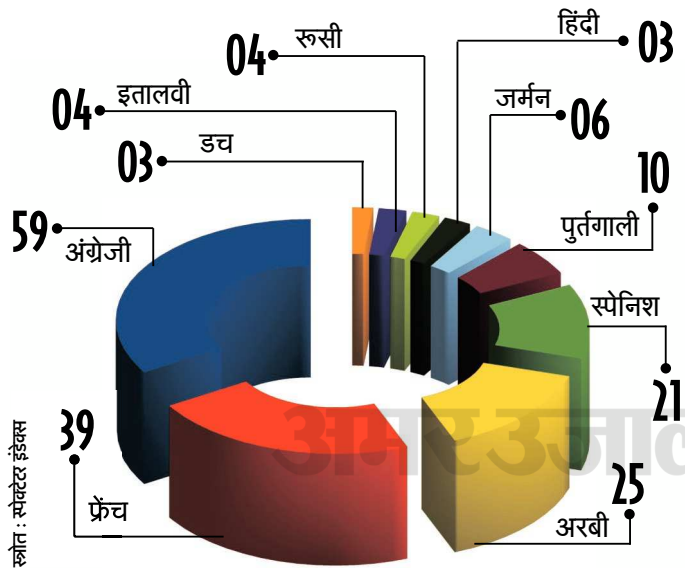

सत्संग

ईश्वर का अस्तित्व

एक बार महर्षि रमण के पास एक युवक आया और बोला, स्वामी जी क्या आप मेरी शंकाओं का निवारण करेंगे? महर्षि ने उत्तर दिया, अवश्य। उस युवक ने पहला प्रश्न किया, इस संसार में इतना घोर अनर्थ कैसे हो रहा है? यह प्रश्न तुम भगवान से क्यों नहीं पूछते, महर्षि ने उससे प्रतिप्रश्न किया।

युवक ने उत्तर दिया, मगर मैं उनके पास जाऊं कैसे? वह दिखाई तो देते नहीं। वास्तव में मुझे उनके अस्तित्व पर ही शंका है। महर्षि ने पुनः उससे प्रश्न किया, भला ऐसी शंका क्यों है तुम्हें? युवक बोला, सीधी-सी बात है। जब तक ईश्वर दिखाई न दे, तब तक कैसे जाना जा सकता है कि ईश्वर भी इस संसार में विद्यमान है?

रमण महर्षि बोले, तुम ठीक कह रहे हो, मगर मेरे प्रश्न का जवाब दो। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? अवश्य, उसने उत्तर दिया। मगर मुझे तो वह दिखाई नहीं देता, महर्षि बोले। तब क्या मैं ऐसी धारणा बना लूं कि तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं?

बस, यही बात ईश्वर के बारे में भी है। जिस प्रकार दिमाग के दिखाई न देते हुए भी हम ऐसी धारणा बना लेते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को दिमाग होता है, उसी प्रकार भगवान के दिखाई न देने पर भी उनके अस्तित्व के बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। वह युवक रमण महर्षि के इस तर्क से संतुष्ट हो प्रसन्नता से वापस लौट गया।

-संकलित